भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या:194

बुधवार, 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

डिजिटल कॉमर्स हेतु ओपन नेटवर्क

***194. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:**
श्री नायब सिंह सैनी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में शुरू किए गए डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) के संबंध में उपलब्धि और सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;
(ख) ई-कॉमर्स के खुले नेटवर्क को अपनाकर छोटे व्यापारियों को किस प्रकार सशक्त बनाए जाने की संभावना है;
(ग) क्या सरकार का छोटे व्यापारियों के लाभार्थ स्थानीय ग्राहकों की सक्रिय भागीदारी को सक्षम बनाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 02.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 194 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : डिजिटल कॉमर्स हेतु ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पहल के अंतर्गत सेक्शन 8 की कंपनी है जिसका उद्देश्य डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन के सभी पहलुओं हेतु ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है।

अब तक की ओएनडीसी की उपलब्धियां:

- पिछले कुछ समय में ओएनडीसी नेटवर्क में दो नई श्रेणियां (एफ एंड बी और ग्रॉसरी) शुरू की गई हैं, तथा श्रेणियों का मोबिलिटी, फैशन, ब्यूटी एवं पर्सनल केयर, होम एण्ड किचन, इलैक्ट्रॉनिक्स और उपकरण, हैल्थ एण्ड वैलनेस तथा बीटूबी तक विस्तार किया गया है।
- ओएनडीसी में नेटवर्क भागीदारों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, तथा नेटवर्क में कई विक्रेता और सेवा प्रदाता शामिल हुए हैं।
- विक्रेता और सेवा प्रदाता 300 से अधिक शहरों में फैले हुए हैं जिससे ओएनडीसी नेटवर्क के भौगोलिक कवरेज में विस्तार हो रहा है।
- पहली बार डिजिटाइज्ड हो रहे विक्रेताओं पर विशेष बल दिया जा रहा है। 'पहली बार डिजिटल' हो रहे विक्रेताओं को ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल करने के लिए विभिन्न स्कीमें तैयार और कार्यान्वित की जा रही हैं।
- ओएनडीसी, एफपीओ और किसानों को नेटवर्क में शामिल करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा नाबार्ड जैसी संस्थाओं के साथ कार्य कर रहा है।
- ओएनडीसी, सिडबी जैसे इकोसिस्टम भागीदारों की सहायता से विभिन्न एसएचजी, सामाजिक क्षेत्र के विक्रेताओं और सूक्ष्म-उद्यमियों को ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
- ओएनडीसी का लाभ उठाने में एमएसएमई की सहायता करने के लिए एक स्कीम तैयार करने हेतु एमएसएमई मंत्रालय के साथ भी ओएनडीसी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। वर्तमान में, विभिन्न एमएसएमई मौजूदा ओएनडीसी विक्रेता एप्स के जरिए ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं।

सरकार ओएनडीसी को बढ़ावा देती है, जो अपनी तरह की पहली वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल कॉमर्स को जन-जन तक पहुंचाना है। सरकार का प्रयास ऐसे बड़े और छोट स्तर के उद्यमियों के बीच समानता लाना और उन्हें एक समान अवसर प्रदान करना है जो वस्तुओं और सेवाओं के प्रभावी आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

(ख) : ई-कॉमर्स हेतु ओपन नेटवर्क अपनाने से छोटे व्यापारियों को विभिन्न तरीकों से सशक्त बनाने में सहायता मिल सकती है:

- छोटे व्यापारी विशिष्ट प्लेटफार्म केंद्रित नीतियों द्वारा शासित होने के स्थान पर किसी भी ओएनडीसी-अनुकूल एप्लीकेशन का उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। यह छोटे व्यवसायियों/व्यापारियों को नेटवर्क में अपनी मौजूदगी दर्शाने तथा व्यवसाय करने के कई विकल्प प्रदान करेगा।

- ओएनडीसी छोटे व्यापारियों को व्यापक उपभोक्ता आधार तक पहुंच वाला नेटवर्क प्रदान करता है और इस प्रकार उनके विकास हेतु अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं।
- ओएनडीसी, बाजार में प्रवेश करने संबंधी प्रमुख बाधाओं को समाप्त करके छोटे व्यापारियों को समान अवसर प्रदान करता है।
- ओएनडीसी सभी व्यवसायों को डिजीटल कॉमर्स में आसानी से भागीदार बनने की सुविधा प्रदान करता है चाहे उनका आकार, स्थान अथवा डिजीटल जानकारी कुछ भी हो।
- ओएनडीसी में शामिल होने के कारण छोटे व्यापारी अधिक लोगों के संपर्क में आ सकते हैं और इससे उन्हें बाजार में अपना ब्रांड लाने में सहायता मिलेगी।
- ओएनडीसी भारत में व्यवसायों की ऊपरी लागत (उदाहरण के लिए अधिग्रहण लागत, डिजीटल मौजूदगी संबंधी लागत) तथा वस्तु सूची संबंधी लागत में कमी के माध्यम से व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।
- ओएनडीसी नेटवर्क के माध्यम से खोज जा सकने वाले छोटे व्यापारी भारत में स्थानीय रूप से विनिर्मित वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों का निवेश और उत्पादन कई गुना बढ़ने की उम्मीद है।
- ओएनडीसी ई-कॉमर्स क्षेत्र में नवप्रयोग को प्रोत्साहित करता है तथा छोटे व्यापारी प्रौद्योगिकीय उन्नति से लाभान्वित हो सकते हैं जिससे उनकी क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी होती है।
- व्यापार के बढ़ने से डिजिटल कॉमर्स मूल्य श्रृंखला जैसे लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, अंतिम छोर तक डिलीवरी आदि में आर्थिक विकास होने और जीवनयापन के अवसरों के सृजन में सहायता मिलने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) : जी, हां। सरकार ओएनडीसी के जरिए छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने तथा स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के महत्व को स्वीकार करती है। सरकार छोटे व्यापारियों के लाभ के लिए निम्नलिखित के जरिए स्थानीय उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव करती है:

- छोटे व्यापारियों की सहायता करने तथा ओएनडीसी नेटवर्क पर उपलब्ध नजदीकी दुकानों से खरीदारी के लिए स्थानीय उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग संघों और सरकार के विभागों के साथ संयुक्त प्रोत्साहन अभियान।
- छोटे व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना जो उनकी डिजिटल उपस्थिति, विपणन रणनीति और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। यह उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा अधिक संख्या में स्थानीय उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की क्षमता रखता है।
- उपभोक्ताओं को ओएनडीसी के बारे में, स्थानीय कारोबारियों की सहायता करने के लाभों और उनके चयन से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूक करना।
- छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए सुगम ई-कॉमर्स लेन-देन में सहायता करने के लिए मजबूत डिजिटल अवसंरचना में निवेश जिसमें विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी, सुरक्षित नेटवर्क और भुगतान गेटवे, स्वचालित शिकायत समाधान तंत्र तथा अंतिम छोर तक डिलीवरी सुविधाएं शामिल हैं।

- ओएनडीसी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। राज्य स्तर पर एंगेजमेंट प्लान में तेजी लाने के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। देशभर में ओएनडीसी संबंधी विभिन्न जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

*****